**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 723**
**गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का विकास

**723. श्रीमती पूनमबेन माडम:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत, संचालित और निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत किए गए कुल निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में विमानपत्तन अवसंरचना विकास में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अंतर्गत देशभर में 25 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है, जिनमें असम में डोलू, ओडिशा में पुरी, तमिलनाडु में परंदुर, राजस्थान में कोटा, गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुरगि, विजयपुरा, हासन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और राजकोट (हीरासर), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगादर्थी, भोगापुरम और ओरावकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर शामिल हैं।

इनमें से 14 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे अर्थात् दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुरगि, ओरवाकल (कुरनूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा, राजकोट (हीरासर), नवी मुंबई और नोएडा (जेवर) को परिचालनरत कर दिया गया है।

(ख): पिछले 5 वर्षों में परिचालनरत किए गए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत अब तक 34,810 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

(ग): सरकार ने देश में हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान करना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा मौजूदा हवाईअड्डों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत असेवित/अल्पसेवित

हवाईअड्डों का विकास/पुनरुद्धार और पीपीपी मोड के माध्यम से मौजूदा और नए हवाईअड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

******